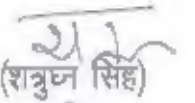


उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा विभाग
संख्या: 263 /1(2)/2008-04(8)-96/2001
देहरादून दिनांक: 29 जनवरी, 2008

अधिसूचना

निजी विकसकताओं के माध्यम से एवं सामुदायिक सहभागिता आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल अधिसूचना सं० 1811/गौ-3-ऊ/2002 दिनांक 19.10.2002 द्वारा निर्गत 25 मेगवाट तक की राज्य की जल विद्युत नीति को अधिकमित करते हुये संशोधित नीति जिसकी प्रति संलग्न है, को इस आदेश की दिशि से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


(शशिल सिंह)
सचिव

संख्या: 263 /1(2)/2008-04(8)-96/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, भ्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (हाइड्रल), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
4. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, 5वां तल, कोर-3, स्वोप कामप्लेक्स, 7 इन्स्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड नियामक आयोग, देहरादून।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल, यूजेवीएन, पिटकूल, देहरादून।
9. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
- ✓ 10. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रालय, रुड़की को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु तथा नीति की 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित प्रेषित।
12. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सी० भास्कर)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड राज्य

निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से एवं
सामुदायिक सहभागिता आधारित
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत
उत्पादन
को बढ़ावा दिए जाने हेतु
नीति

उत्तराखण्ड सरकार

निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने हेतु नीति

1. प्रस्तावना:

उत्तराखण्ड राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की बहुत अधिक सम्भावनाएँ हैं। इन पर्यावरणीय अनुकूल लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट क्षमता तक) की स्थापना से अधिकतर स्रोतों का दोहन किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में अभी 20000 मेगावाट से भी अधिक विद्युत उत्पादन की सम्भावनाएँ हैं।

इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायोमास, कृषि अपशिष्ट, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नगरीय अपशिष्ट, सह-उत्पादन आदि पर आधारित सूक्ष्म, अति लघु, एवं लघु विद्युत परियोजनाएँ स्थापित की जा सकती हैं। इस नीति के माध्यम से विभिन्न प्रदूषण रहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का दोहन एवं उपयोग कर राज्य के दूरस्थ एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत उत्पादन करने तथा वर्ष 2020 तक विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के माध्यम से 1000 मेगावाट क्षमता से अधिक की विद्युत परियोजनाएँ विकसित कराया जाना है।

2. उद्देश्य:

उत्तराखण्ड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र (Private Sector)/ सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के अनुकूल शर्तों/नियमों का निर्धारण किया जाना। मुख्यतः

- 2.1 पर्यावरणानुकूल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन एवं राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इनके योगदान को बढ़ावा दिया जाना।
- 2.2 आत्मनिर्भर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (Renewable Energy Projects) के माध्यम से न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति एवं विकल्पों का निर्धारण।
- 2.3 कृषि औद्योगिक, व्यावसायिक/वाणिज्यिक एवं घरेलू क्षेत्रों को विकेंद्रीकृत विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना।
- 2.4 ग्रिड विद्युत उत्पादन की गुणवत्ता में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (RF Projects) के माध्यम से सुधार किया जाना।
- 2.5 इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराना जो पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में सहायक हो।
- 2.6 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नयी एवं उभरती हुई तकनीकीयों का विकास, प्रदर्शन एवं वाणिज्यीकरण में सहायता किया जाना एवं राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त एवं सहयोगी प्रतिष्ठानों की स्थापना में सहयोग किया जाना।

- 2.7 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (RE Projects) में निजी निवेशकर्ताओं (Private Investors) की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुकूल शर्तों/नियमों का निर्धारण किया जाना।
- 2.8 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रति जन-जागरण एवं स्थानीय उपभोगताओं/समुदाय की क्षमतावृद्धि करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के रख-रखाव एवं अन्य विकास कार्यों में भागीदारी कराया जाना।
- 2.9 राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अवसरों का सृजन।

3. प्रस्तावित कार्यनीति

उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रोत्साहित किए जाने के लिए निम्न कार्यनीति प्रस्तावित है:-

- सूक्ष्म/लघु जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन।
- गन्ना, कागज, उर्वरक एवं रासायनिक उद्योगों आदि में सह-उत्पादन (Co-generation)
- शायोमास/कृषि अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन।
- शहरी, नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन।
- सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन।
- वायु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन।
- जियोथर्मल ऊर्जा से विद्युत उत्पादन।
- घरेलू, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक एवं परिवहन क्षेत्रों में ऊर्जा बचत हेतु कठोर प्रशासनिक/वैधानिक/न्यायिक नियमों/तकनीकी उपायों को सरकारी क्षेत्रों से आरम्भ करते हुए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु लागू किया जाना।

4. दोहन हेतु प्रस्तावित स्रोत

उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं राज्य में उपलब्ध विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का आधार पर राज्य सरकार निम्न क्षेत्रों में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा निवेश को सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर देते हुए प्रोत्साहित करना:-

4.1 जल विद्युत ऊर्जा:-

उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक संरचना के अनुसार प्रचुर मात्रा में छोटे-2 झरने, गदरों एवं नदियां हैं जिनमें वर्षभर पानी उपलब्ध रहता है। उपलब्ध जल बहाव से वर्ष 2020 तक अनुमानित अनुप्रयुक्त 600 मे0वा0 विद्युत उत्पादन की सम्भावनाएँ हैं। राज्य सरकार अनुप्रयुक्त जल बहाव से ऊर्जा उत्पादन हेतु बचनबद्ध है।

4.2 सह-उत्पादन:-

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक अनेकों औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हो चुकी हैं जिनका विस्तार किया जा रहा है। राज्य में स्थापित चीनी, कागज, उर्वरक, रासायनिक, कपड़ा एवं अन्य उद्योगों में सह-उत्पादन किए जाने हेतु अनुमानित 220 मे0वा0 विद्युत उत्पादन के स्रोत

उपलब्ध हैं। इन उद्योगों/इकाईयों द्वारा सह-उत्पादन को अपनाये जाने से राज्य को अतिरिक्त विद्युत प्राप्त होने के साथ-2 कंपटिव उत्पादन भी हो सकेगा। सह-उत्पादन के स्रोतों का वर्ष 2020 तक पूर्ण रूप से दोहन किया जायेगा।

4.3 बायोमास एवं कृषि अपशिष्ट ऊर्जा:-

उत्तराखण्ड राज्य में बायोमास से विद्युत उत्पादन की सम्भावनायें हैं। अनुमानतः प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलियन टन कृषि अपशिष्टों एवं कृषि आधारित उद्योगों से अपशिष्टों के रूप में प्राप्त होता है। इन अपशिष्टों से लगभग 300 मेगवाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। राज्य सरकार इन स्रोतों का वर्ष 2020 तक दोहन किए जाने हेतु सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

4.4 शहरी, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस एवं तरल अपशिष्टों ऊर्जा

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1000 मीट्रिक टन शहरी, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस एवं तरल अपशिष्टों का उत्पादन हो रहा है। इन अपशिष्टों का वैज्ञानिक विधि द्वारा निराकरण करते हुए पर्यावरण के शुद्ध होने के साथ-2 विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। प्रारम्भिक तौर पर इस प्रकार की छोटी-2 परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहयोग किया जायेगा।

4.5 सौर ऊर्जा

राज्य में सौर ऊर्जा का प्रचुर स्रोत उपलब्ध है एवं राज्य सरकार इन स्रोतों का दोहन करने हेतु इच्छुक है। राज्य सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करायेगी।

4.6 वायु ऊर्जा

राज्य में वायु ऊर्जा के प्रयाप्त मात्रा में अनुप्रयुक्त स्रोत उपलब्ध हैं। उपलब्ध स्रोतों के दोहन हेतु विण्ड मैपिंग की तत्काल आवश्यकता है। राज्य सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करायेगी।

4.7 जियोथर्मल ऊर्जा

राज्य में जियोथर्मल ऊर्जा के प्रयाप्त मात्रा में अनुप्रयुक्त स्रोत उपलब्ध हैं। उपलब्ध स्रोतों के मापन/दोहन की आवश्यकता है। राज्य में उपलब्ध स्रोतों के अधिकाधिक उपयुक्त दोहन हेतु जियोथर्मल ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

4.8 ऊर्जा संरक्षण

राज्य में घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से 20 प्रतिशत तक विद्युत की खपत में बचत की जायेगी। राज्य सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण कराए जाने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में स्थित ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों जिनका विद्युत भार 25 कि0वाट से अधिक है, में ऊर्जा ऑडिट को अनिवार्य बनाया जायेगा। इस कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त कार्यप्रणाली को अपनाया जायेगा।

5. प्रोत्साहन

- 5.1** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को क्रय करने का प्रथम अधिकार यू0पी0सी0एल0 को दिया जायेगा। यू0पी0सी0एल0 को कुल उत्पादित विद्युत अथवा उसके एक भाग को अपनी आवश्यकता के अनुसार सम्बन्धित उत्पादनकर्ता से क्रय करने का अधिकार होगा। क्रय की जाने वाली विद्युत का मूल्य उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू0ई0आर0सी0) द्वारा अग्रिम रूप से निर्धारित किया जायेगा जो ऐसे सभी उत्पादनकर्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। यू0पी0सी0एल0 द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत बिलों के भुगतान की गारन्टी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जायेगी।
- 5.2** यू0पी0सी0एल0/पिटकुल द्वारा उत्पादनकर्ता को उसके जैपटिव उपयोग, तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु अथवा राज्य के बाहर विद्युत उपयोग हेतु आवश्यक विद्युत पारेषण एवं वितरण लाईनें उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित उत्पादनकर्ता को व्हीलिंग शुल्क (Wheeling Charges) का भुगतान किया जाना होगा। व्हीलिंग शुल्क के सम्बन्ध में अलग से अग्रिम रूप से सूचित किया जायेगा जो ऐसे सभी उत्पादनकर्ताओं पर समान रूप से लागू होगा।
- 5.3** यू0पी0सी0एल0 द्वारा उत्पादनकर्ताओं को आपसी सहमत शर्तों पर वीरिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5.4** उत्पादित विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित किए जाने के लिए उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0)/पावर ट्रॉंसमिशन कर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल) के माध्यम से आवश्यक विद्युत पारेषण एवं वितरण लाईनों की व्यवस्था करायी जायेगी।
- 5.5** नगरीय ठोस अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन की स्थिति में यदि सरकारी भूमि (स्थानीय निकाय/पंचायत के स्वामित्व में) उपलब्ध हो, तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि न्यूनतम लीज रेंट रु0 1/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से 33 वर्षों हेतु लीज पर दी जायेगी। यह लीज अवधि आपसी सहमति से आगे विस्तारित की जा सकती है।

6. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमति/स्वीकृति

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की स्थापना हेतु विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों से अनुमति/स्वीकृति की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध रूप से "एकल खिड़की व्यवस्था" आधार पर अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस हेतु उच्च स्तरीय सक्षम समिति का गठन किया जायेगा। प्रस्तावित सक्षम समिति का विवरण अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध है।



7. परियोजनाओं का वर्गीकरण

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार से किया जायेगा:-

(अ) जल ऊर्जा परियोजनाएँ (25 मे0वा0 क्षमता तक)

(ब) अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ जिनमें सह-उत्पादन, बायोमास/कृषि अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन, शहरी, नगरीय एवं औद्योगिक तरल / ठोस अपशिष्टों, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण सम्मिलित है।

7(अ) जल ऊर्जा परियोजनाएँ

- (1) उत्पादन क्षमता के अनुरूप परियोजनाओं का वर्गीकरण निम्न तीन श्रेणियों में किया जायेगा:-

क) 100 कि0वा0 क्षमता तक की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएँ।

ख) 100 कि0वा0 से अधिक एवं 5 मे0वा0 क्षमता तक की अति लघु जल विद्युत परियोजनाएँ।

ग) 5 मे0वा0 क्षमता से अधिक एवं 25 मे0वा0 क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाएँ।

- (2) परियोजनाओं के चिन्हीकरण के अनुरूप परियोजनाओं का वर्गीकरण निम्न दो श्रेणियों में किया जायेगा:-

क) स्वयं चिन्हित परियोजनाएँ:- विकासकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं का चिन्हीकरण डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य स्वयं किया जायेगा तदोपरान्त उसके आवंटन हेतु आवेदन किया जायेगा।

ख) राज्य द्वारा चिन्हित परियोजनाएँ:- राज्य अथवा राज्याधीन संस्थाओं द्वारा किसी भी क्षमता तक की चिन्हित परियोजनाएँ।

परियोजनाओं का आवंटन

स्वयं चिन्हित परियोजनाएँ:-

अर्हताएँ:-

सूक्ष्म परियोजनाओं हेतु

(i) वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो।

(ii) परियोजना स्थल के आस-पास उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायत हो।

- (iii) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 / उ०प्र० कोपरेटिव सोसाइटी एक्ट - 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था जो उत्तराखण्ड में स्थित हो, परियोजना आवंटन हेतु अर्ह होंगे।

सूक्ष्म परियोजनाओं हेतु

- (i) वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो,
- (ii) परियोजना स्थल के आस-पास उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायत हो,
- (iii) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 / उ०प्र० कोपरेटिव सोसाइटी एक्ट - 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था जो उत्तराखण्ड में स्थित हो,
- (iv) कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म जिनकी उत्पादन इकाईयां उत्तराखण्ड राज्य में स्थित हो,

को परियोजना आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी।

लघु परियोजनाओं हेतु

यह सभी के लिये खुली हुई रखी गई हैं, इन पर कोई आरक्षण नहीं है। इसके लिये प्रोपोज़िशन का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया:-

सम्भावित विकासकर्ताओं की उपयुक्तता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

- (क) तकनीकी क्षमता, जिसमें पूर्व वर्षों में ऊर्जा परियोजना के विकास/निर्माण/संचालन का अनुभव सम्मिलित होगा, के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी क्षमता के आकलन हेतु अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए गये हैं।
- (ख) वित्तीय क्षमता का आकलन परियोजना के निर्माण में पूंजी लागत तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण कराए जा सकने की क्षमता के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम वित्तीय क्षमता सूक्ष्म परियोजनाओं हेतु रुपये दस लाख तथा अति लघु परियोजनाओं हेतु रुपये पचास लाख होनी चाहिए। (साक्ष्य हेतु हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)। वित्तीय क्षमता के आकलन हेतु अधिकतम 40 अंक निर्धारित किए गये हैं।

जमा की जाने वाली धनराशि:-

सभी भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किए जायेंगे। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी किये गये हो।

आवेदन शुल्क (Non-refundable) ₹ 5000/-

प्रोसेसिंग शुल्क (परियोजना विकास अनुबंध हस्ताक्षर के समय देय):

- ❖ सूक्ष्म परियोजना हेतु : ₹0 10,000 / -
- ❖ अति लघु परियोजनाओं हेतु : ₹0 25,000 / -
- ❖ लघु परियोजनाओं हेतु : ₹0 50,000 / -

सिक्युरिटी धनराशि (परियोजना क्रियान्वयन अनुबंध हस्ताक्षर के समय देय):

- ❖ सूक्ष्म परियोजना हेतु : ₹0 20,000 / -
- ❖ अति लघु परियोजनाओं हेतु : ₹0 50,000 / -
- ❖ लघु परियोजनाओं हेतु : ₹0 1,00,000 / -

राज्य चिन्हित परियोजनाएँ:-

लघु जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन निविदा आधार पर बिना किसी आरक्षण के किया जायेगा।

अर्हता एवं मूल्यांकन प्रक्रिया:-

अर्हता एवं मूल्यांकन शर्तों का विवरण आर0एफ0क्यू0/आर0एफ0पी0/निविदा प्रपत्र में दिया गया है।

आवंटन प्रक्रिया:-

चिन्हित परियोजनाओं के आवंटन हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की जायेंगी। निविदाओं का दो स्तरीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होगा:-

1. **प्री-क्वालिफिकेशन:-** आवेदनकर्ता की उपयुक्तता का निर्धारण आर0एफ0क्यू0 प्रपत्र में दिए गए मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा जिसमें मुख्यतः बैलेंस शीट, वार्षिक रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता आदि सम्मिलित होंगी। मूल्यांकन के आधार पर सफल विकासकर्ताओं की छटनी कर सूचीबद्ध किया जायेगा।
2. **वित्तीय बिड:-** छटनी के उपरान्त सूचीबद्ध किए गए विकासकर्ताओं से वित्तीय प्रस्ताव (आर0एफ0पी0) आमंत्रित किए जायेंगे। वित्तीय प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम के आधार पर जमा किए जायेंगे (ऐसे वित्तीय प्रस्ताव, जो न्यूनतम प्रीमियम से कम पाये जायेंगे, निरस्त कर दिए जायेंगे)। राज्य सरकार की ओर से निम्नानुसार न्यूनतम प्रीमियम निर्धारित किया गया है:-

- ❖ 2 मे0वा0 क्षमता से अधिक एवं 5 मे0वा0 क्षमता तक: ₹0 एक लाख प्रति मे0वा0
- ❖ 5 मे0वा0 क्षमता से अधिक एवं 25 मे0वा0 क्षमता तक: ₹0 पाँच लाख प्रति मे0वा0

3. अधिकतम प्रीमियम धनराशि देने वाले निविदादाता को परियोजना आवंटित की जायेगी। सफल निविदादाता द्वारा प्रीमियम धनराशि को निविदा प्रपत्र में दी गयी समयावधि में राज्य सरकार को जमा कराया जाना होगा।
4. परियोजनाओं के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता अपनायी जायेगी इस हेतु आर०एफ०यू०/ आर०एफ०पी०/बिड प्रपत्र में सभी तकनीकी एवं वित्तीय सूचनाएँ उपलब्ध होंगी।

7(ब) अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ

अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनायें सभी श्रेणी के विकासकर्ताओं को स्वयं चिन्हित आधार पर आवंटित की जायेंगी अथवा जहाँ सम्भव हो टैरिफ निर्धारण आधार पर आवंटित की जायेंगी।

टैरिफ निर्धारण आधार पर परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण अलग से किया जायेगा। स्वयं चिन्हित परियोजनाओं का आवंटन निम्नानुसार मूल्यांकन आधार पर किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया :-

सम्भावित विकासकर्ताओं की उपयुक्तता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

- (क) तकनीकी क्षमता, जिसमें पूर्व वर्षों में ऊर्जा परियोजना के विकास/निर्माण/संचालन का अनुभव सम्मिलित होगा, के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी क्षमता के आंकलन हेतु अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए गये हैं।
- (ख) वित्तीय क्षमता का आंकलन परियोजना के निर्माण में पूंजी लागत तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण कराए जा सकने की क्षमता के आधार पर किया जायेगा। वित्तीय क्षमता के आंकलन हेतु अधिकतम 40 अंक निर्धारित किए गये हैं।

जमा की जाने वाली धनराशि:-

सभी मुग्तान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किए जायेंगे। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गये हों।

आवेदन शुल्क (Non-refundable) ₹ 5000/-

प्रोसेसिंग शुल्क (परियोजना विकास अनुबंध हस्ताक्षर के समय देय):

❖ 1 मे०वा० क्षमता तक परियोजना हेतु ₹ 10,000/-

❖ 1 मे०वा० से अधिक क्षमता की परियोजनाओं हेतु ₹ 25,000/-

सिक्युरिटी धनराशि (परियोजना क्रियान्वयन अनुबंध हस्ताक्षर के समय देय):

❖ 1 मे0वा0 क्षमता तक परियोजना हेतु : ₹0 20,000/-

❖ 1 मे0वा0 से अधिक क्षमता की परियोजनाओं हेतु: ₹0 60,000/-

8. क्लीन डैवलपमेन्ट मैकेनिज़्म (सी0डी0एम0) के अन्तर्गत लाभ :-

इस नीति के अन्तर्गत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली ऊर्जा अन्य पारम्परिक स्रोतों के सापेक्ष सस्ती न होने के दृष्टिगत इन पर्यावरणीय अनुकूल परियोजनाओं के विकास पर सी0डी0एम0 के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विकासकर्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

9. विविध:-

- 9.1 किसी भी विकासकर्ता को पैराग्राफ 4.1 से 4.8 तक अंकित प्रत्येक ऊर्जा स्रोत पर आधारित अधिकतम 3 परियोजनाओं का ही आवंटन किया जायेगा।
- 9.2 ऐसी औद्योगिक इकाइयों जो उत्तराखण्ड में स्थित हैं तथा निविदा आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना आवंटन कराकर उत्पादित विद्युत का उपयोग अपनी औद्योगिक इकाई हेतु करना चाहती हैं, जो उनके द्वारा बोली गयी बिड धनराशि (Bid Amount) अधिकतम बिड धनराशि (Bid Amount) के 80 प्रतिशत तक होने पर परियता प्रदान की जायेगी।
- 9.3 राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन किसी भी संस्था को किसी भी परियोजना के आवंटन अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 9.4 अगर किसी उपयुक्त सूक्ष्म, अति लघु एवं लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कोई उपयुक्त विकासकर्ता उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसी दशा में उक्त परियोजना निविदा आधार पर आवंटित की जा सकेगी। इस हेतु अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जायेंगे।
- 9.5 अगर कोई विकासकर्ता परियोजना आवंटन के उपरान्त परियोजना निर्माण के विभिन्न स्तरों को निर्धारित समय के अन्तर्गत बिना किसी वैध कारण से पूर्ण नहीं करता है तो उक्त विकासकर्ता द्वारा जमा की गयी प्रीमियम/सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं परियोजना का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9.6 इस नीति की अधिसूचना की तिथि से पूर्व जो परियोजनाएँ आवंटित की जा चुकी हैं वे इस नीति में प्रस्तावित प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।
- 9.7 अगर कोई विकासकर्ता परियोजना आवंटन के उपरान्त परियोजना की क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित विकासकर्ता से अतिरिक्त वृद्धित क्षमता (Additional enhanced capacity) पर 1 मे0वा0 से 5 मे0वा0 क्षमता तक ₹0 1,00,000/- प्रति मे0वा0 की दर से तथा 5 मे0वा0 से अधिक क्षमता पर ₹0 5,00,000/- प्रति मे0वा0 की दर से धनराशि अतिरिक्त रूप से प्राप्त की जायेगी। राज्य द्वारा चिन्हित ऐसी परियोजना जिसका आवंटन निविदा आधार पर

किया गया हो। की क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव पर अतिरिक्त वृद्धित क्षमता की प्रीमियम का निर्धारण अलग से फार्मूला आधार पर किया जायेगा।

9.8 अगर कोई विकासकर्ता (परियोजना की कमीशनिंग से पूर्व) आवंटित परियोजना को किसी अन्य विकासकर्ता को किसी कारणवश विक्रय किया जायेगा तो ऐसी दशा में सम्बन्धित विकासकर्ता से उसके द्वारा जमा की गयी बिड धनराशि (Bid Premium) की 100 प्रतिशत समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

9.9 परियोजनाये आवटन की तिथि से 40 वर्ष तक विकासकर्ता को दी जायेगी तदोपरान्त परियोजनाये राज्य सरकार को वापिस हो जायेंगी अथवा राज्य सरकार की सहमत शर्ता पर अवधि बढ़ाई जा सकेंगी।

9.10 रॉयल्टी :-

❖ सूक्ष्म, अति लघु एवं अन्य वैकल्पिक उर्जा परियोजनाये जो इस उर्जा नीति के अन्तर्गत होंगी पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जायेगी।

❖ लघु जल विद्युत परियोजनाये जो इस उर्जा नीति के अन्तर्गत होंगी पर प्रथम 15 वर्षों के संचालन पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जायेगी परन्तु 16वें वर्ष से विद्युत उत्पादन पर 18 प्रतिशत की रॉयल्टी ली जायेगी।

10. नीति में संशोधन/शिथिलता/स्पष्टीकरण:-

इस नीति में निर्धारित नियमों में संशोधन/शिथिलता/स्पष्टीकरण के समस्त अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित हैं।

11. नीति के लागू होने की तिथि:-

यह नीति एवं प्रोत्साहन (Incentives) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से जारी अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगी।

१०

सक्षम समिति (EMPOWERED COMMITTEE) का गठन

सक्षम समिति के घटक (Composition of Empowered Committee):-

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्तावों पर स्वीकृति के लिए प्रशासनिक सचिवों की निम्नानुसार सक्षम समिति (Empowered Committee) गठित की जाती है:-

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि०	सदस्य
9.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०	सदस्य
10.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल	सदस्य
11.	उपाध्यक्ष, यू०आई०पी०सी०	सदस्य
12.	निदेशक, उरेडा	सदस्य सचिव

समिति अन्य सचिव/राज्य सरकार के अधिकारी/विषय विशेषज्ञों, जब एवं जितने आवश्यक हों, को समिति में सम्मिलित कर सकती है।